लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अधिक राशि का आबंटन

*238. **श्री विनोद शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गयी धनराशि की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक राशि रखने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछली राशि की तुलना में यह राशि कितनी अधिक है ;

(ग) क्या सरकार ने इस अवधि के दौरान रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने और इस क्षेत्र के लिए निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) जी, हां । अस्थायी परिव्यय के अनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के लघु उद्योगों के लिए लगभग 2812 करोड़ रु० की धनराशि का प्रावधान है । सातवीं योजना में यह धनराशि 1120.51 करोड़ रु० थी ।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस क्षेत्र के लिए 150 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है । जिसमें योजनावद्ध के दौरान 24.50 लाख की वृद्धि भी शामिल है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस क्षेत्र से निर्यात के 20000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

Discrimination against PSU in awarding contracts

*239. SHRI ASHIS SEN:
SHRI SUNIL BASU RAY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the *Economic Times* dated 5th June, 1992 regarding efforts to scuttle PSUs by foreign funding agencies;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether it is a fact that public sector units are being discriminated on the instructions of foreign funding agencies in matters of awarding contracts despite submitting lowest bids; and

(d) if so, whether this is against the national interest?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) The request of Mining & Allied Machinery Corporation Ltd (MAMC), Durgapur for acceptance of their offers for Package-I & II of the Coal Handling Plant of North Madras Thermal Power Station of Tamil Nadu Electricity Board against global tender and Package-I Group C of Coal Handling Plant for Raichur TPS Unit aided by OCF, Japan, was taken up with the State of Tamil Nadu and Karnataka.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.